Dr. S. S. Pandey

TOPIC

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) योजना

AMRUT योजना

- परिचय
- उद्देश्य
- प्रमुख लक्षण / प्रावधान
- सुझाव

परिचय / Introduction

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी विकास हेतु एक योजना का प्रारंभ– 25 जून, 2015

उद्देश्य / Objective

छोटे शहरों एवं कस्बों को या फिर शहर के कुछ अनुभागों को चुनकर वहाँ पर बुनियादी सुविधाएँ स्थापित करना

प्रमुख लक्षण / प्रावधान
Key Features / Provisions

1. इस योजना के तहत शहरी कस्बों या क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएँ; जैसे– बिजली, सप्लाई पानी, सिवरेज, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, परिवहन, हरित स्थल एवं पार्क, क्षमता निर्माण आदि के विकास का प्रावधान
2. बिजली बिल, पानी बिल, हाउस टैक्स आदि का भुगतान E-Governance के माध्यम से
3. यह योजना एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों, छोटी नदी के किनारे वाले नगरों, पर्यटन संभावित पहाड़ी इलाकों एवं द्वीप वाले क्षेत्रों में लागू
4. प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत 'नगर इकाई कमेटियों' (City Unit Committees) के गठन का प्रावधान
5. इस परियोजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान
6. योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने वाले राज्यों के लिए बजट में 10% तक के आवंटन का प्रावधान
7. 2020 तक इस योजना के तहत 500 शहरों को कवर करने का लक्ष्य
8. JNNURM के अंतर्गत अधूरी रह रही परियोजनाओं को 2017 तक पूरा करने का प्रावधान
9. 2019 में– अमृत योजना के लक्ष्य को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया

अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग

Ranking of States Under AMRUT Scheme

1. अगस्त 2020 में– आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है
2. ओडिशा ने 85.67% स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया
3. चंडीगढ़ एवं तेलंगाना को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है और इसके बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान है

समीक्षा

Evaluation

निश्चित रूप से AMRUT योजना शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है जिसके लिए भारतीय प्रधान मंत्री ने नारा दिया है कि– "मेरा देश बदल रहा है... आगे बढ़ रहा है।" परन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि– इसको कितनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जा रहा है

Dr. S. S. Pandey

Smart City Mission - 2015

परिचय

Introduction

1. 25 जून, 2015 को शहरी विकास से संबंधित एक प्रमुख योजना की घोषणा– Smart City Mission
2. 17 जून, 2016 को मुम्बई में 'स्मार्ट सिटी शिखर सम्मेलन' जिनमें 20 शहरों को को चुना गया, जिन्हें प्रथम चरण में स्मार्ट सिटी बनाया जाना था
3. 25 जून, 2016 को नरेन्द्र मोदी ने पूणे में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम का प्रारंभ

उद्देश्य

Objective

2030 तक 40% नगरीय आबादी की संभावना को देखते हुए, ऐसे नगरीय विकास को बढ़ावा देना– जो नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराकर एक उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान कराने हेतु तथा लोगों एवं निवेश को आकर्षित करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है

प्रमुख लक्षण / प्रावधान

Key Features / Provisions

1. नगर में मूलभूत सेवाओं की उच्च गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि का प्रावधान
2. विविध प्रकृति के शहर के विकास का प्रावधान
3. टिकाऊ एवं समावेशी विकास पर विशेष बल और पर्यावरण प्रदूषण मुक्त शहर के विकास का प्रावधान
4. 2015-16 से 2019-2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने पर बल (2016 में 20, 2017 में 40, 2018 में 40)
5. 5 वर्षों में 48000 करोड़ रुपये (प्रतिवर्ष प्रतिशहर 100 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा तथा इतना ही संबंधित राज्य सरकार द्वारा धन का आवंटन
6. Digital India, skill Development Programme, AMRUT योजना, हृदय योजना, PM आवास योजना आदि द्वारा वित्त की आपूर्ति का प्रावधान
7. पीपीपी के तहत विकास

चुनौतियाँ

Challenges

1. कम बजट / वित्त की समस्या– मात्र 1000 करोड़ प्रति स्मार्ट सिटी धन का आवंटन– बहुत ही कम (जबकि दक्षिण कोरिया के Songdo शहर का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास 15000 एकड़ में– लागत 35000 करोड़)

2. निजी निवेश से संबंधित समस्या (वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार– PPP in Water Supply के संदर्भ में भारत के 57 पीपीपी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर इस क्षेत्र में निवेश हेतु आगे नहीं आया)

3. पीपीपी की समस्या– (Mckinsey के रिपोर्ट के अनुसार– शहरीय निकाय में प्रतिव्यक्ति आय मात्र 1400 रुपये व खर्च 6000 रुपये अर्थात प्रत्येक शहर घाटे में)

4. विगत् कई वर्षों से रियल स्टेट घाटे में फलतः निजी निवेश की समस्या

5. नीति निर्माण एवं कार्यक्रम समुचित क्रियान्वयन की समस्या [अप्रैल 2018 – शहरी विकास संबंधी संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट – 2015 से स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जारी की गयी राशी (9943.22 करोड़ रुपये) में से केवल 1.8% (182 करोड़ रुपये) का उपयोग किया गया]

6. ग्रामीण नगरीय प्रवास की समस्या

7. चुने गए शहरों का पुराना एवं असमान होना

8. भ्रष्टाचार की समस्या

9. राज्य में एवं शहरी स्थानीय निकाय में कुशल नेतृत्व का अभाव

सुझाव

Suggestion

1. नए शहरों के विकास पर बल दिया जाय (साऊथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग से 200 किमी. बाहर वर्ल्ड कप का आयोजन और वहाँ स्मार्ट सिटी का निर्माण सफल– लंदन से बाहर ओलम्पिक का आयोजन और वहाँ स्मार्ट सिटी का निर्माण सफल)

2. संतुलित एवं अनुकूल नीति एवं योजना का निर्माण तथा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ भ्रष्टाचारमुक्त क्रियान्वयन

3. स्थानीय निकायों की सोच एवं नेतृत्व को अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धी बनाया जाए

4. वित्त निर्माण पर बल तथा साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी संतुलित व नियंत्रित हो ताकि समावेशी विकास संभव हो सके

5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन तथा मनरेगा के सफल क्रियान्वयन द्वारा ग्रामीण विकास को तीव्र किया जाय

स्मार्ट सिटी मिशन : नई डिजिटल पहल

Smart City Mission : New Digital Initiative

हाल ही में नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण करने की दिशा में शहरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए आदर्श स्थिति पैदा करने के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (National Urban Digital Mission) की शुरूआत की गई है।

इसके साथ ही इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज (आईयूडीएक्स), स्मार्टकोड, स्मार्ट सिटी 2.0 वेबसाइट और भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस) जैसी कई अन्य पहल को भी लॉन्च किया गया।

इन पहलों के जरिए अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरों को अधिक आत्मनिर्भर और सक्षम बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (National Urban Digital Mission - NUDM)

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) शहरों और नगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म जैसे तीन स्तंभों पर काम करते हुए शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करेगा।

इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज (IUDX)

आईयूडीएक्स एक ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो विभिन्न डाटा प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी प्रमाणन एवं अधिकृत एप्लिकेशंस और अन्य स्रोतों के बीच डाटा के सुरक्षित, प्रमाणित और व्यवस्थित आदान-प्रदान की सुविधा देता है।

स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म Smart Code Platform

1. स्मार्टकोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो शहरी शासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी इकोसिस्टम हितधारकों को विभिन्न समाधानों और एप्लिकेशंस के लिए ओपन-सोर्स कोड के भंडार में योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है।
2. इसे उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनका सामना शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शहरी चुनौतियों का समाधान निकालते समय डिजिटल एप्लिकेशंस को विकसित करने और इन्हें लागू करने के दौरान किया जाता है।

न्यू स्मार्ट सिटी वेबसाइट वर्जन 2.0 और जीएमआईएस New Smart City Website Version 2.0 and GMIS

1. यह वेबसाइट स्मार्ट सिटी से संबंधित पहलों के लिए सिंगल स्टॉप की तरह काम करेगी।
2. वेबसाइट के साथ भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीएमआईएस) को जोड़ा गया है।
3. यह वेबसाइट स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission) के लिए एक सिंगल विंडो की सुविधा प्रदान करती है। यह एक ऐसा पोर्टल है, जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू किए गए सभी प्लेटफार्मों और पहलों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है।

वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021

Global Smart Cities Index 2021

1. वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 के मुताबिक भारतीय शहरों के सूचकांक में गिरावट आई है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आईएमडी) ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एंड डिजाइन (एसयूटीडी) के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 जारी किया है।

2. वैश्विक स्मार्ट सिटी की सूची में चार भारतीय शहर– हैदराबाद तथा दिल्ली के रैंकिंग में गिरावट हुई है, वहीं मुंबई तथा बेंगलुरु के रैंकिंग में अंशतः सुधार हुआ हैदर्ज की गई है, जबकि सिंगापुर इस सूची में शीर्ष पर रहा है।

3. वर्ष 2021 के स्मार्ट सिटी सूचकांक में हैदराबाद का स्थान 92वां (2020 में 85 स्थान) रहा है। नई दिल्ली को 89वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल उसका स्थान 86वां था। इस सूचकांक में मुंबई 2020 के 93वें स्थान से कुछ सुधार कर 2021 में 90वें स्थान पर आ गया, जबकि बेंगलुरु को 93वां स्थान मिला है। (2020 में – 95वाँ स्थान)

4. कुछ भारतीय शहरों को इस साल रैंकिंग में मामूली गिरावट तो कुछ शहरों के रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है। इसकी वजह यह हो सकती है कि जहाँ तकनीकी विकास नहीं हुआ है, वहाँ महामारी का प्रभाव ज्यादा रहा है।

5. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय शहर महामारी से अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे। स्मार्ट सिटी सूचकांक (एससीआई) 2021 में सिंगापुर सबसे ऊपर है, उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख और ओस्लो रहे हैं।

Dr. S. S. Pandey

PURA (Providing Urban Amenities in Rural Areas)

PURA

- परिचय
- उद्देश्य
- प्रमुख प्रावधान/लक्षण
- समीक्षा

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन- 2015

परिचय
Introduction

ग्रामीण विकास हेतु निर्मित एक प्रमुख योजना जिसको 16 सितम्बर, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी / घोषणा और 21 फरवरी, 2016 को PM द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के Kurubhat गाँव से रुरबन मिशन का प्रारंभ

उद्देश्य
Objective

ग्रामीण इलाकों में शहर की तरह आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी संरचना विकास को प्रोत्साहित करना तथा सरकार को शामिल करते हुए 'स्मार्ट गाँव' का निर्माण करना

प्रमुख प्रावधान / लक्षण
Key Provisions / Features

1. गाँव में शहरों जैसी 12 बुनियादी सुविधाएँ; जैसे- स्वास्थ्य सुविधा, सप्लाई पानी, सफाई एवं कूड़ा प्रबंधन, सूचना तकनीक आदि उपलब्ध कराना

2. बुनियादी संरचना के विकास के साथ कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमिता पर विशेष बल देते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना

3. 2019-2020 तक 300 क्लस्टर्स (प्रत्येक में 25 से 50 गाँव शामिल) के विकास का प्रावधान तथा पहले चरण में 100 क्लस्टर्स के विकास का प्रावधान

4. इस क्लस्टर्स में 25 से 50 गाँव शामिल जिसमें मैदानी एवं तटीय क्षेत्रों में 25,000 से 50,000 जनसंख्या तथा पहाड़ी, रेगिस्तानी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 5000 से 15000 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को शामिल करने का प्रावधान

5. इस मिशन हेतु केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा 5142 करोड़ रुपये की मंजूरी

6. इस मिशन हेतु केन्द्र द्वारा 30% वित्तीय सहायता का प्रावधान तथा पंचायत स्तर पर मौजूद अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं से खर्च की आपूर्ति का प्रावधान

समीक्षा एवं सुझाव

Evaluation and Suggestions

निश्चित रूप से ग्रामीण विकास द्वारा ग्रामीण-नगरीय प्रवास को रोकने और अतिनगरीकरण के समस्या समाधान में यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो एक तरफ, ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीण-नगरीय विषमता को दूर करके एक संतुलित विकास की ओर उन्मुख है तो दूसरी ओर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना...

...SCM की सफलता हेतु एक पूर्वशर्त के रूप में क्रियाशील है अर्थात इस योजना को सफल बनाकर ही SCM के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

परन्तु इसके लिए निम्न सुझावों पर अमल जरूरी है-

1. दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ क्रियान्वयन

2. इस योजना हेतु समुचित वित्त की व्यवस्था हो और विद्यमान वित्त का भ्रष्टाचार मुक्त प्रयोग

3. आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करके निजी क्षेत्रों को आकर्षित किया जाए क्योंकि इस योजना की दीर्घकालीन निरंतरता हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता जरूरी

4. पंचायती राज के कुशल नेतृत्व द्वारा इस योजना में सहयोगी भूमिका को प्राप्त किया जाए

5. इस योजना को राजनीतिकरण से बचाया जाए

तभी आदर्श गाँव के लक्ष्य को प्राप्त करके 'भारत' और 'इण्डिया' के बीच की खाई को दूर किया जा सकता है।

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

भारत में अतिनगरीकरण की समस्या

Problem of Over-urbanization in India

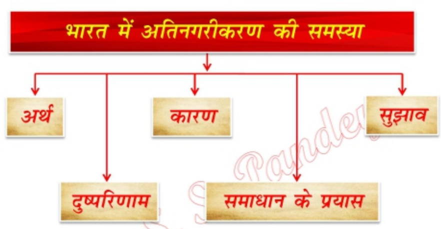

भारत में अतिनगरीकरण का अर्थ

Meaning of Urbanization in India

किसी भी नगर की आर्थिक क्षमता एवं संरचनात्मक सुविधाओं की क्षमता से ज्यादा जनसंख्या का नगर में आ जाना अतिनगरीकरण (Over-Urbanisation) – कहलाता है

भारत में अतिनगरीकरण के दुष्परिणाम

Side Effects of Over-urbanization in India

1. आवास की समस्या (1.87 करोड़ आवास की कमी तथा 32% लोग एक कमरे वाली घर में रहते हैं– अमिताभ कुंडु समिति की रिपोर्ट) तथा गंदी बस्ती की समस्या (10.36 करोड़ जनसंख्या गंदी बस्तियों में रहती हैं) तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक समस्या
2. सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या (केवल 30% के पास नल वाला पानी), मल निकासी की समस्या (18.6 करोड़ के पास शौचालय नहीं तथा 13% के पास नहाने की सुविधा नहीं)
3. पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं सांस्कृतिक प्रदूषण (LIR, यौन संबंधों में खुलापन, Valentine Day आदि) की समस्या
4. प्रभावी एवं पर्याप्त परिवहन की समस्या
5. इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या
6. बेरोजगारी, नगरीय गरीबी एवं जीवन निर्वाह नगरीकरण की समस्या
7. नगरीय भूमि की दुर्लभता, कृषि भूमि का अतिक्रमण जिससे खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी समस्या

भारत में अतिनगरीकरण के कारण

Causes for Over-urbanization in India

1. तीव्र जनसंख्या में वृद्धि
2. ग्रामीण विकास की धीमी गति फलतः तीव्र ग्रामीण-नगरीय प्रवास
3. नगरों में तीव्र औद्योगिकीकरण (Rapid Industrialization) व रोजगार की उपलब्धता
4. नगरों की तुलना में गाँवों में संरचनात्मक सुविधाओं (Structural Features) की धीमी गति

5. नगरीय संस्कृति का आकर्षण
6. ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती प्रवृत्ति, अस्पृश्यता, जाति-संघर्ष एवं नक्सलवाद
7. नगरों में बढ़ती जनसंख्या की तुलना में रोजगार के अवसर व संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की धीमी गति

भारत में अतिनगरीकरण की समस्या समाधान के प्रयास

Efforts to Solve the Problem of Over-urbanization in India

1. सरकार द्वारा स्थापित परिवार विमर्श केन्द्र तथा NGO के माध्यम से निःशुल्क सुझाव एवं सहायता केन्द्र
2. नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना
3. 1962 में नगर नियोजन संगठन की स्थापना एवं 1957 में प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास प्राधिकरण (UDA) का गठन
4. शहरी भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण एवं नियमन अधिनियम, 1976 द्वारा भूमि के संतुलित वितरण का प्रयास
5. 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा नगरीय विकास एवं मलिन बस्तियों में जीवन स्तर में सुधार का प्रयास
6. दिल्ली हेतु 'राष्ट्रीय राजधानी नियोजन मण्डल' (National Capital Planning Board) तथा 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (National Capital Region) (1985) की स्थापना
7. 74वां संविधान संशोधन के रूप में प्रयास
8. PURA (2003) तथा RURBAN Mission (2015) का क्रियान्वयन
9. आवास की समस्या निवारण हेतु 'राष्ट्रीय आवास बैंक' (National Housing Bank) की स्थापना तथा 'प्रधानमंत्री आवास योजना (2015)' (Pradhan Mantri Awas Yojana) का क्रियान्वयन
10. राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति एवं परिवहन की समस्या समाधान हेतु प्रयास
11. पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा पर्यावरणीय समस्या समाधान हेतु प्रयास
12. स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2013 (Street Vendors Act, 2013) द्वारा स्ट्रीट वेंडर की समस्या का समाधान

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

भारत में अति-नगरीकरण एवं खाद्य सुरक्षा की समस्या

Problem of Over-urbanization and Food Security in India

भूमिका

Introduction

1. अति-नगरीकरण भारतीय नगरीकरण की प्रमुख विशेषता है
2. अति-नगरीकरण की इस प्रक्रिया ने कई रूपों में भारत में खाद्य सुरक्षा (Food Security) की समस्या को उत्पन्न किया है

भारत में अति-नगरीकरण का खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव

Impact of Over-urbanization on Food Grain Production in India

1. नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण नगर के आस-पास के कृषि भूमि का आवासीय (Residential) क्षेत्र में परिवर्तन
2. आवासीय भूमि के मूल्य में वृद्धि व कृषि भूमि का तेजी से विक्रय
3. रियल स्टेट से जुड़ी कंपनियों द्वारा उच्च दरों पर कृषि भूमि की खरीद और आधुनिक आवासीय परिसरों का निर्माण
4. सरकार द्वारा नगर नियोजन तथा प्रति-नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या SEZ आदि लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण
5. ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय संस्कृति के प्रसार के कारण, ग्रामीणों में कृषि कार्य से अलगाव तथा ग्रामीण-नगरीय प्रवास के कारण ग्रामीण कृषि मजदूरों का शहरों की ओर पलायन– फलतः कृषि कार्य दुष्प्रभावित

समीक्षा

Evaluation

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि निश्चित रूप से अति-नगरीकरण ने खाद्य सुरक्षा (Food Security) के संदर्भ में चिंता को उत्पन्न किया है। परन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि यह समस्या संक्रमणकालीन अवस्था एवं असंतुलित विकास का परिणाम है।

इन समस्याओं से मुक्त निराकरण के लिए जरूरी है कि- भूमि की अधिग्रहण नीति को अनुकूल बनाया जाए या कृषि भूमि अधिग्रहण को रोका जाए कृषि नीति को कृषकों के अनुकूल बनाया जाए और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए; श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन द्वारा गाँव में......

...रोजगार एवं संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करके एवं कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करके 'भारत' और 'India' के बीच की खाई को समाप्त किया जाए।

- भारत में अति-नगरीकरण ने भारतीय खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं को विस्तारित किया

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

भारत में गंदी बस्ती की समस्या

Slums Problem in India

भारत में गंदी बस्ती की समस्या

- अर्थ
- कारण
- प्रयास
- स्वरूप
- दुष्परिणाम
- मूल्यांकन एवं सुझाव

गंदी बस्ती का अर्थ

Meaning of Slums

नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित आवासीय समूह जिसका स्तर अत्याधिक निम्न होता है, गंदी बस्ती (Slums) कहलाता है।

2001/2011 की जनगणना के अनुसार– एक छोटे घने क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कम से कम 300 या लगभग 60-70 गरीब परिवार जो कि अस्वास्थ्यकर वातावरण में सामान्यतः अनुपयुक्त आधारभूत सुविधाएँ जैसे- पीने का पानी एवं सफाई सुविधा के अभाव में निवास करते हैं, को चिह्नित गंदी बस्ती माना जाएगा।

भारत में गंदी बस्ती का स्वरूप

Form of Slums in India

गंदी बस्तियों का विकास भारतीय नगरीकरण की एक प्रमुख समस्या है, जहाँ 2001 में 6.18 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में रहते थे वहीं 2011 में यह संख्या 10.36 करोड़ हो गयी है (कुल नगरीय जनसंख्या का 27.5%)

1. भारत के गंदी बस्तियों में रहने वाले कुल आबादी का 57% तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रहते हैं।
2. भारत में गंदी बस्ती में रहने वाले 35% घरों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है।
3. भारत के गंदी बस्तियों में 63% घरों से गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है।

गंदी बस्ती के दुष्परिणाम / समस्यात्मक पक्ष

Side Effects / problematic Aspects of Slums

1. स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव
2. श्रमिकों की कार्यक्षमता पर दुष्प्रभाव
3. व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय पर दुष्प्रभाव
4. विभिन्न प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि एवं विकास
5. संस्कृति पर दुष्प्रभाव अर्थात् सांस्कृतिक अपघटन

गंदी बस्तियों के विकास के कारण

Causes to Development of Slums

1. ग्रामीण-नगरीय प्रवास (National Institute for Urban Affairs)
2. नगर में आवास की अपर्याप्तता (NIUA)
3. नगर भूमि नीति (NIUA)
4. नगरीय गरीबी, बेरोजगारी एवं निम्न मजदूरी
5. मुद्रास्फीति एवं महँगा किराया
6. स्लम माफिया

भारत में गंदी बस्तियों के उन्मूलन / समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास

Efforts Made to Eradicate Slums / Problem Solution in India

प्रत्यक्ष प्रयास / Direct Effort

1. विभिन्न सरकारी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा स्लम के लोगों की आवश्यकतापूर्ति और समस्या समाधान की दिशा में किए गए प्रयास
2. राजीव आवास योजना 2011
3. स्लममुक्त भारत मिशन 2013
4. सबके लिए आवास योजना 2015

परोक्ष प्रयास / Indirect Effort

1. Counter Urbanization / प्रति नगरीकरण तथा नगरों के बाहरी क्षेत्र एवं Satellite Town का विकास करके / साथ ही NCR विस्तार योजना के द्वारा- नगरीय आबादी को नगर से बाहर की ओर विकेन्द्रित करने के रूप में किया गया प्रयास
2. ग्रामीण विकास के द्वारा ग्रामीण- नगरीय प्रवास को रोकने हेतु किए गए प्रयास

मूल्यांकन एवं सुझाव

Evaluation and Suggestions

1. निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों के द्वारा स्लम की समस्या समाधान की दिशा में प्रगति हुई है

2. परन्तु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और 2001 की तुलना में 2011 में स्लम की जनसंख्या (10.36 करोड़/कुल नगरीय आबादी का 27.5%) बढ़ी है

3. इसका प्रमुख कारण आर्थिक सुधार (1991) के बाद ग्रामीण-नगरीय विषमता में वृद्धि फलतः तीव्र ग्रामीण- नगरीय प्रवास है

4. इसलिए एक तरफ ग्रामीण-नगरीय प्रवास को रोककर तो दूसरी तरफ गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों को आवास एवं रोजगार उपलब्ध कराकर, समस्या का स्थाई समाधान किया जा सकता है।

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

राजीव गाँधी आवास योजना - 2011

Rajiv Gandhi Housing Scheme - 2011

राजीव गांधी आवास योजना-2011

- परिचय
- उद्देश्य
- प्रमुख प्रावधान / लक्षण
- समीक्षा

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन - 2013

Slums Free India Mission - 2013

मलिन बस्ती मुक्त भारत मिशन - 2013

- परिचय
- उद्देश्य
- प्रमुख प्रावधान/लक्षण
- समीक्षा

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

सबके लिए आवास योजना - 2015

Housing for All Scheme - 2015

सबके लिए आवास योजना - 2015

- परिचय
- उद्देश्य
- लक्षण / प्रावधान
- समीक्षा

परिचय

Introduction

2015 में प्रारंभ नगरीय गरीबों के आवास विकास हेतु एक कार्यक्रम

उद्देश्य

Objective

स्लमवासियों के साथ-साथ शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता को पूरा करना तथा 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना

लक्षण / प्रावधान

Characteristics / Provisions

1. *भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए, निजी भागीदारी से, स्लमवासियों हेतु स्लम पुनर्वास का प्रावधान*
2. *ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से, कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन*
3. *सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) के तहत, किफायती आवास उपलब्ध कराना*
4. *इस योजना से लाभान्वित वही व्यक्ति होगा जिसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी भाग में अपना मकान नहीं होगा।*
5. *इस योजना के तहत 9 राज्यों के 305 शहरों की पहचान और 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य*

   (26 दिसम्बर, 2018 को शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की रिपोर्ट- इस योजना के तहत तीन वर्षों में 58 हजार घर बनाने का लक्ष्य, परन्तु मात्र 31000 घरों का निर्माण पूरा हुआ)

हाल में प्रधान मंत्री आवास योजना के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा Performance Index जारी किया गया है। इसके अनुसार- वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए-

1. झारखण्ड 82.46% अंक के साथ प्रथम स्थान पर
2. राजस्थान 82.14% अंक के साथ द्वितीय स्थान पर
3. मध्य प्रदेश 76.06% अंक के साथ तृतीय स्थान पर रहा है

समीक्षा

Evaluation

निश्चित रूप से उपरोक्त योजना / मिशन नगरीय स्लम आवास से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें पहले से संचालित राजीव गांधी आवास योजना और स्लम मुक्त भारत मिशन की कमियों को दूर करते हुए,

आवास निर्माण की स्व-अभिप्रेरणा में वृद्धि तथा निजी भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ नगरीय भूमि को संसाधन के रूप में प्रयोग करने पर बल देकर, नगरीय विकास के अन्य घटकों के साथ इसे एकीकृत करने का प्रयास किया गया है।

परन्तु इस मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें जनसहभागिता को बढ़ाते हुए, नियंत्रित एवं संतुलित पीपीपी के तहत, भ्रष्टाचारमुक्त रूप से एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाए।

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

भारत में ग्रामीण- नगरीय प्रवास

Rural-urban Migration in India

भारत में ग्रामीण-नगरीय प्रवास

- प्रवास का अर्थ
- भारत में प्रवास का स्वरूप
- भारत में ग्राम नगरीय प्रवास का स्वरूप
- ग्राम-नगरीय प्रवास के परिणाम
- ग्रामीण-शहरी प्रवास के कारण
- ग्रामीण-शहरी प्रवास को रोकने हेतु सुझाव

प्रवास का अर्थ

Meaning of Migration

जब कोई व्यक्ति या समूह मुख्यतः रोजगार हेतु किसी नये स्थान पर एक सप्ताह या उससे अधिक अधिवास का काम करता है, तो इसको प्रवास की संज्ञा दी जाती है।

भारत में प्रवास का स्वरूप

Form of Migration in India

1. ग्राम-ग्राम प्रवास
2. ग्राम-नगरीय प्रवास
3. नगरीय-नगरीय प्रवास
4. नगरीय-ग्राम प्रवास

भारत में ग्राम-नगरीय प्रवास का स्वरूप

Form of Rural-urban Migration in India

1. मुख्यतः विमारू राज्यों से 2.5 लाख दिल्ली में प्रति वर्ष
2. मुख्यतः विमारू राज्यों से 1.5 लाख मुंबई व गुजरात में प्रति वर्ष
3. मुख्यतः विमारू राज्यों से 50,000 पंजाब में कृषि कार्य करने हेतु प्रति वर्ष

भारत में ग्राम - नगरीय प्रवास के परिणाम / प्रभाव

Consequences / Effects of Rural-urban Migration in India

1. नगरीय समाज पर प्रभाव
2. ग्रामीण समाज पर प्रभाव

ग्रामीण-शहरी प्रवास के कारण

Causes for Rural-urban Migration

धकेलने वाले कारक / Push Factors

1. ग्रामीण विकास की धीमी गति और समुचित रोजगार का अभाव
2. ग्रामीण क्षेत्र में सामंती प्रवृत्ति, अस्पृश्यता, जाति संघर्ष एवं नक्सलवाद
3. नगरों की तुलना में गाँवों में अवसंरचनात्मक (Infrastructural) सुविधाओं की धीमी गति

खींचने वाले कारक / Pull Factors

1. नगरों में तीव्र औद्योगीकरण एवं रोजगार की उपलब्धता
2. नगरीय संस्कृति का आकर्षण
3. नगरो में समानता युक्त महौल में काम करने का अवसर

भारत में ग्रामीण - नगरीय प्रवास को रोकने हेतु किए गए प्रयास

Efforts Made to Stop Rural-urban Migration in India

1. गाँव पर समग्र विकास पर बल और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
2. मनरेगा
3. PURA
4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन

Dr. S. S. Pandey

TOPIC

नगरीकरण / नगरों से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास

Efforts Made to Solve Urbanization / Other Problems Related to Cities

1. शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास (Efforts Made to Eradicate Urban Poverty)
   - स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (1997)
   - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2014)

2. शहरी पर्यावरण की समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास (Efforts Made to Solve the Problems of Urban Environment)
   - 1974 में– पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन
   - 2010 में– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान नियम
   - यूरो-VI – मानक को संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य कर दिया गया

- मुख्यत: दिल्ली में जनहित याचिका के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए प्रयास– ओखला की जगह नोयडा का विकास; CNG की अनिवार्यता तथा दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए प्रयास

3. शहरी स्वास्थ्य विकास हेतु किये गये प्रयास (Efforts Made for Urban Health Development)

- 1986– राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन
- 1990– राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन
- 2012– राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण
- 2008– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति का निर्माण
- 2013– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता मिशन
- 20 अक्टूबर, 2014– स्वच्छ भारत अभियान

4. शहरों की सामाजिक समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयास (Efforts Made to Solve Social Problems of Cities)

- परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना
- नशाखोरी उन्मूलन केन्द्र की स्थापना
- सरकार एवं NGO द्वारा अनाथालयों एवं वृद्धाश्रम की स्थापना
- शहरी वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन
- सामुदायिक एकीकरण (Community Integration) हेतु सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन

संभावित प्रश्न

- अमृत योजना के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए नगरीय समस्याओं के समाधान में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।
- SCM भारतीय शहरों को किस प्रकार स्मार्ट बनाने में सक्षम होगा? इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए इसकी चुनौतियों को दर्शाइए।
- SCM शहरी विकास से संबंधित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस मिशन को सफल बनाने के मार्ग में कौन-कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। उत्तर दीजिए और इस मिशन को सफल बनाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत कीजिए।
- भारत में ग्रामीण-नगरीय प्रवास अतिनगरीकरण को संभव बनाकर नगरीय समस्याओं के उद्भव एवं विकास में आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। ग्रामीण-नगरीय प्रवास की समस्या का समाधान किस प्रकार SCM की सफलता हेतु जरूरी है? स्पष्ट कीजिए और ग्रामीण-नगरीय प्रवास को रोकने हेतु उपाय सुझाइए।
- क्या आप सहमत हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-नगरीय मिशन की सफलता SCM की सफलता की एक पूर्वशर्त है? आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन को सफल बनाने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए।

- भारत में स्मार्ट शहरों के विकास हेतु स्मार्ट गाँवों का विकास भी एक आवश्यक शर्त है। इस कथन के प्रकाश में SCM की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाइए।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। यह किस प्रकार ग्रामीण विकास में सहायक होगा? उत्तर दीजिए।

- सबके लिए आवास योजना/पीएम आवास योजना शहरी आवास की समस्या के समाधान की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस कथन को सविस्तार प्रतिपादित कीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए।

- गंदी बस्ती की समस्या समकालीन भारत में शहरी समस्या का एक प्रमुख स्वरूप है। इस समस्या के उद्भव के कारणों की चर्चा कीजिए और इसके उन्मूलन के दिशा में किए गए प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
- भारत में शहरीकरण से संबंधित सामाजिक – सांस्कृतिक समस्याओं की सूची बनाइए और इनके उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।